दैनिक
क्रांति समय
RNI.No. : GUJHIN/2018/75100
संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
सूरत, वर्षः 02 अंकः 287, मंगलवार, 15 अक्टुबर, 2019, पेजः 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिसः- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कांग्रेस पर फिर फूटा निरुपम का गुस्सा, पूछा- राहुल की रैली में निकम्मा कहां था?

नेशनल डेस्क। कांग्रेस पार्टी के अंदर के कलह किसी से छुपे नही है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने पिछले कुछ समय से पार्टी के प्रति बगावती तेवर अख्तियर किए हुए हैं। अब निरुपम ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर एक ट्वीट किया है जो नए विवाद को पैदा कर सकता है। कांग्रेस नेता ने सोमवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी की मुंबई रैली में मेरी अनुपस्थिति को लेकर जो बातें की जा रही हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं। एक पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से मैं पूरे दिन व्यस्त रहा था और इस बारे में मैंने राहुल गांधी को पहले ही बता दिया था। वो मेरे नेता हैं और वह हमेशा ही मेरे लिए एक जैसे रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा'..लेकिन निकम्मा अनुपस्थित क्यों था? माना जा रहा है कि संजय निरुपम का यह तंज कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा को लेकर था। बता दें कि संजय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे से नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी निशाने पर लेते हुए कहा था कि पार्टी में चुगली करने वालों का बोलवाला है और राहुल गांधी के करीबियों को जानबूझ कर किनारे किया जा रहा है।

भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डफ्लो को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

स्टॉकहोम। भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार फ्रांस की एस्थर डफ्लो और अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 'वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया। नोबेल समिति के सोमवार को जारी एक बयान में तीनों को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। बयान के मुताबिक, ''इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं का शोध वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने में हमारी क्षमता को बेहतर बनाता है। मात्र दो दशक में उनके नये प्रयोगधर्मी दृष्टिकोण ने विकास अर्थशास्त्र को पूरी तरह बदल दिया है। विकास अर्थशास्त्र वर्तमान में शोध का एक प्रमुख क्षेत्र है। बनर्जी, 58 वर्ष, ने भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद 1988 में उन्होंने हावर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। वर्तमान में वह मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के फोर्ड फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं। बनर्जी ने वर्ष 2003 में डुफ्लो और सेंडिल मुल्लइनाथन के साथ मिलकर अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब (जे-पाल) की स्थापना की। वह प्रयोगशाला के निदेशकों में से एक हैं। बनर्जी संयुक्तराष्ट्र महासचिव की '2015 के बाद के विकासत्मक एजेंडा पर विद्वान व्यक्तियों की उच्च स्तरीय समिति% के सदस्य भी रह चुके हैं।

मुंबईः अंधेरी में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, 13 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला बाहर

मुंबई। मुंबई के अंधेरी में सोमवार को एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू के जरिए इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग लगने से उठा धुंआ आसपास के इलाके में भी फैल गया जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बता दें कि इससे पहले रविवार को मुंबई के ग्रांट रोड पर पांच मंजिली इमारत में आग लग गई। आग लगने के बाद आठ-दस लोग खुद ही बाहर निकल आए जबकि नौ लोगों को दमकलकर्मियों ने बाहर निकाला।

मिलकर भी हम न मिले...महाराष्ट्र में बीजेपी - शिवसेना साथ, पर पोस्टरों में नहीं

मुम्बई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हमेशा चर्चा का विषय रहता है। दोनों पार्टियों के गठबंधन में होने के बावजूद ऐसे बयान और तस्वीरें नजर आती रहती हैं, जो ऑल इज नॉट वैल की बहस को जन्म देती हैं। अब जबकि मतदान का वक्त नजदीक है और दोनों पार्टियां मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं तो ऐसे में भाजपा और शिवसेना के पोस्टरों ने सबका ध्यान खींचा है। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा और शिवसेना ने जो पोस्टर लगाए हैं, उनमें गठबंधन की जगह 'एकला चलो रे' की झलक दिखाई दे रही है। मुम्बई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों के होर्डिंग्स अलग-अलग नजर आ रहे हैं। शिवसेना के पोस्टर में बाला साहेब, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दिखाई दे रहे हैं तो भाजपा के पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस प्रमुखता से नजर आ रहे हैं, यानी दोनों पार्टियों के नेता पोस्टरों में एक साथ नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि देवेंद्र फडनवीस के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना की सरकार 5 साल चली है, लेकिन सरकार के कामकाज को भी भाजपा-शिवसेना ने संयुक्त रूप से नहीं दर्शाया। गठबंधन के ऐलान के साथ ही कहा गया था कि भाजपा और शिवसेना का घोषणा-पत्र एक साथ जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना ने अपना अलग घोषणा-पत्र जारी कर दिया और अपने एजेंडे के तहत गरीबों को पौष्टिक भोजन 10 रुपए में देने और सिर्फ 1 रुपए में 200 स्वास्थ्य परीक्षण कराने जैसे वादे किए हैं। भाजपा जहां देवेंद्र फडनवीस को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश कर चुकी है, वहीं शिवसेना की नजर भी सरकार के शीर्ष पद पर है। शिवसेना के पोस्टरों में ठाकरे परिवार से पहली बार चुनाव लड़ रहे आदित्य ठाकरे को भी इसी अंदाज में पेश किया जा रहा है।

सोनिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस, कहा- जनता सिखाएगी खट्टर को सबक

नेशनल डेस्क (एजेंसी)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कथित तौर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ी खबर को लेकर कांग्रेस ने कहा कि इस असंसदीय एवं निंदनीय बयान के लिए खट्टर को देश की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने यह दावा भी किया कि इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की महिलाएं खट्टर को उनकी महिला विरोधी सोच के लिए सबक सिखाएंगी। कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ अपने तुच्छ बयान, महिलाओं के अपमान और असामाजिक सोच के लिए मुख्यमंत्री खट्टर को देश की समस्त महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर जी, आपके लिए महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपने सोनिया जी के खिलाफ जो टिप्पणी की है वह पूरे नारी समाज का घोर अपमान है। आपके शासन में हरियाणा क्राइम कैपिटल बन गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की आधी आबादी आगामी 21 अक्टूबर को आपको सबक सिखाने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने एक बयान जारी कर कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टिप्पणी की निंदा करती हूं। उनकी टिप्पणी असंसदीय और निंदनीय है। यह महिलाओं के प्रति उनके और भाजपा के अपमानजनक रुख को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विमर्श के स्तर को नीचे ले जाना बेरोजगारी और गंभीर आर्थिक मंदी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि हरियाणा भारत की रेप कैपिटल बन चुका है। अपहरण के मामले बहुत बढ़ गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है। खबरों के मुताबिक खट्टर ने एक सभा में कथित तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया ।

और कहा कि नया कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा... हमने इस निर्णय का स्वागत किया था... वंशवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए यह अच्छा फैसला था... फिर, इन लोगों ने देशभर में नए अध्यक्ष की तलाश शुरू की... तीन महीने के बाद, उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया... यह तो ऐसा हुआ, जैसे खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वह भी मरी हुई।

खालिस्तान'पर खुल कर बोले भारतीय राजदूत, कहा- जनमत संग्रह 2020 बेकार का मुद्दा

वाशिंगटन। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि ''मुट्ठीभर सिखों द्वारा समर्थित 'जनमत संग्रह 2020 एक ''बेकार का मुद्दा है जिसे भारत विरोधी एक पड़ोसी देश समर्थन दे रहा है। श्रृंगला ने रविवार को कहा कि इसे वे मुट्ठीभर लोग समर्थन दे रहे हैं जिन्हें समुदाय का ''बहुत ही कम समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के समूह ''आतंकवादी कृत्य कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है, जब किसी शीर्ष भारतीय राजदूत ने 'जनमत संग्रह 2020 के खिलाफ खुले तौर पर कुछ कहा है। खालिस्तान के गठन को लेकर अलगाववादी सिख 'जनमत संग्रह 2020 को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने बाल्टीमोर में एक गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ''(जनमत संग्रह के) प्रायोजक मुट्ठीभर लोग हैं। तथाकथित जनमत संग्रह 2020 बेकार का मुद्दा है। श्रृंगला ने कहा, ''वे हताश हो रहे हैं और आतंकवाद एवं उग्रवादी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अतीत की बात हो जाएगी। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जनमत संग्रह का मामला उठाने वालों को पाकिस्तान के एजेंट बताया। श्रृंगला ने कहा, ''जैसा कि हम जानते हैं कि इन लोगों को हमारा वह पड़ोसी देश समर्थन दे रहा है, जो लगातार हमारा विरोधी रहा है।और दुष्प्रचार किया है। उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों ''हम बड़े समुदाय के साथ काम करना जारी की पारम्परिक पगड़ी और सफेद कुर्ता एवं पायजामा पहने राजदूत ने 'सिख एसोसिएशन ऑफ बाल्टीमोर गुरुद्वारा एवं 'सिख्स ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सिख समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने समुदाय की समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। श्रृंगला ने कहा कि पटल पर अब और मुद्दे नहीं हैं। ' 'और जो मुद्दे हैं भी, (भारत) सरकार उनके लिए समुदाय के साथ मिलकर काम करने को पूरी तरह तैयार है।

सोनिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस, कहा- जनता सिखाएगी खट्टर को सबक

नेशनल डेस्क (एजेंसी)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कथित तौर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ी खबर को लेकर कांग्रेस ने कहा कि इस असंसदीय एवं निंदनीय बयान के लिए खट्टर को देश की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने यह दावा भी किया कि इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की महिलाएं खट्टर को उनकी महिला विरोधी सोच के लिए सबक सिखाएंगी। कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ अपने तुच्छ बयान, महिलाओं के अपमान और असामाजिक सोच के लिए मुख्यमंत्री खट्टर को देश की समस्त महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर जी, आपके लिए महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपने सोनिया जी के खिलाफ जो टिप्पणी की है वह पूरे नारी समाज का घोर अपमान है। आपके शासन में हरियाणा क्राइम कैपिटल बन गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की आधी आबादी आगामी 21 अक्टूबर को आपको सबक सिखाने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने एक बयान जारी कर कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टिप्पणी की निंदा करती हूं। उनकी टिप्पणी असंसदीय और निंदनीय है। यह महिलाओं के प्रति उनके और भाजपा के अपमानजनक रुख को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विमर्श के स्तर को नीचे ले जाना बेरोजगारी और गंभीर आर्थिक मंदी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि हरियाणा भारत की रेप कैपिटल बन चुका है। अपहरण के मामले बहुत बढ़ गए हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है। खबरों के मुताबिक खट्टर ने एक सभा में कथित तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया और कहा कि नया कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा... हमने इस निर्णय का स्वागत किया था... वंशवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए यह अच्छा फैसला था... फिर, इन लोगों ने देशभर में नए अध्यक्ष की तलाश शुरू की... तीन महीने के बाद, उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया... यह तो ऐसा हुआ, जैसे खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वह भी मरी हुई।

थाईलैंड ने पाक को सौंप दिया दाऊद का करीबी साथी मुन्ना, भारत हैरान

दुबई (एजेंसी)।

थाईलैंड ने दाउद इब्राहिम के करीबी शूटर मुन्ना झिंगड़ा उर्फ मोहम्मद सलीम पर चल रहे मुकदमे में कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे 9 अक्तूबर को पाकिस्तान को सौंप दिया। थाईलैंड के इस कदम से भारत और थाईलैंड के रिश्तों में खटास आ सकती है। थाईलैंड के अखबार द नेशन थाईलैंड ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि हम थाईलैंड की न्याय प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें इस फैसले से हैरानी हुई है। भारत ऐसे में थाईलैंड के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा कर सकता है। बता दें बैंकॉक एक दोषी अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच फंसा था। गौरतलब है दाऊद के गुर्गे मुन्ना का केस थाईलैंड की अदालत में भारत के खिलाफ गया था। इसके बाद अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण के निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया था। अदालत के नए आदेश के तहत मुन्ना को 9 अक्तूबर को पाकिस्तान को प्रत्यर्पित कर दिया गया। वहीं भारत की ओर से दावा किया गया था कि झिंगड़ा एक भारतीय नागरिक है। झिंगड़ा को सईद मुजक्किर मुदस्सर हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। झिंगड़ा के प्रत्यर्पण के लिए भारत पिछले दो साल से थाईलैंड के उच्च अधिकारियों के संपर्क में था। थाईलैंड की कोर्ट ने माफिया डॉन छोटा राजन पर हमला करने का दोषी पाते हुए झिंगड़ा को 35 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में अदालत ने इस सजा को कम करके 16 साल कर दिया था। थाईलैंड की जेल में अपनी सजा काटने के बाद उसे 2016 में जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि भारत ने उसकी रिहाई से पहले ही 2012 में थाईलैंड से उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। भारत पहले ही छोटा राजन को प्रत्यर्पित करा चुका है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम पर मुंबई में हुए 1993 के बम धमाकों का आरोप है। इस हमले में 257 लोग की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। गौरतलब है कि इधर भारत कई बार पाकिस्तान को दाऊद को सौंपने के लिए कह चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक उसे नहीं सौंपा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार भी कहते आए हैं ।

70 दिन बाद कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरू, प्रीपेड यूजर्स को अभी करना होगा इंतजार

श्रीनगर (एजेंसी)।

कश्मीर घाटी में बीएसएनएल नेटवर्क की पोस्ट पेड मोबाइल सेवा सोमवार को बहाल हो गई। करीब 70 दिनों पर घाटी में आज से मोबाइल फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गईं। आज दोपहर को कश्मीर में 40 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव हो गए। दो दिन पहले फैसला लिया गया था कि घाटी से पोस्टपेड सेवाओं पर लगी पाबंदी हटा ली जाएगी। फिलहाल पोस्टपेड मोबाइल पर कॉलिंग की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया गया है। मोबाइल इंटरनेट के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही सरकार प्रीपेड सेवा भी बहाल करने पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से 5 अगस्त को एहतियात के तौर पर मोबाइल फोन सेवाएं और इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया था। हालांकि जम्मू और लद्दाख में मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई थीं लेकिन कश्मीर में बैन लगा हुआ था। आने वाले 31 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। घाटी में 17 अगस्त तक लैंडलाइन की आंशिक सेवा बहाल की गई थीं और 4 सितंबर तक करीब 50,000 लैंडलाइन को शुरू करने की घोषणा की गई थी। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवा अगस्त मध्य से बहाल हो गई थी। मोबाइल सेवा इससे भी पहले चालू हो चुकी थी। हालांकि दुरुपयोग होने के बाद 18 अगस्त को मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा को फिर से बंद कर दिया गया था।

अयोध्या केसः

मुस्लिम पक्ष के वकील बोले- सिर्फ हमसे ही सवाल पूछे जा रहे, हिंदू पक्ष से क्यों नहीं?

अयोध्या (एजेंसी)।

दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है। 38वें दिन की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विवादित इमारत पर हमेशा से मुसलमानों का कब्जा बता रहे मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन से सवाल किया कि जब बाहरी हिस्से में हिंदू राम चबूतरा और सीता रसोई बनाकर पूजा करते थे, फिर यहां आपका कब्जा कैसे हुआ? इस पर धवन ने कहा कि विचित्र बात है कि सिर्फ मुस्लिम पक्षकारों से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरे पक्ष से कोर्ट सवाल नहीं करता। सारे सवाल सिर्फ हमसे ही किए गए हैं। निश्चित ही हम उनका जवाब देंगे। धवन के इस कथन का रामलला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने जोरदार प्रतिवाद किया और कहा, 'यह पूरी तरह से अनावश्यक है। धवन ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब संविधान पीठ ने कहा कि विवादित स्थल पर लोहे की ग्रिल लगाने का मकसद बाहरी बरामद से भीतरी बरामदे को अलग करना था। कोर्ट ने कहा कि लोहे का ग्रिल लगाने का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों को अलग-अलग करना था और यह तथ्य सराहनीय है कि हिंदू बाहरी बरामदे में पूजा-अर्चना करते थे जहां 'राम चबूतरा, 'सीता रसोई 'भंडार गृह थे। शीर्ष अदालत ने धवन के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि हिंदुओं को सिर्फ अंदर प्रवेश करने और स्थल पर पूजा-अर्चना करने का 'निर्देशात्मक अधिकार था और इसका मतलब यह नहीं है कि

विवादित संपत्ति पर उनका मालिकाना हक था। पीठ ने सवाल किया कि जैसा आपने कहा कि उनके पास प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार था, क्या यह आपके मालिकाना अधिकार को कमतर नहीं करता। पीठ ने यह भी कहा कि संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के मामले में क्या किसी तीसरे पक्ष को प्रवेश और पूजा-अर्चना का अधिकार दिया जा सकता है। अयोध्या विवाद के संभावित फैसले को लेकर 10 दिसंबर तक अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम अनुज कुमार झा ने बताया कि अयोध्या विवाद के संभावित फैसले, दीपोत्सव, चेहल्लुम व कार्तिक मेले को लेकर 2 महीने तक जनपद में धारा-144 लागू रहेगी।

अयोध्या फैसले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है।

बाबरी मामले पर फैसला आने से पहले अयोध्या में प्रशासन अलर्ट पर, धारा 144 लागू

नई दिल्ली। अयोध्या-बाबरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी अनुज झा ने कहा कि अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और दीपावली महोत्सव पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को समाप्त होगी। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद मामले में छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं।

संपादकीय

खोज का नोबेल नुस्खा

जब एक करियर के रूप में विज्ञान की बात आती है, तो इसे एक ऐसे दिलचस्प काम की तरह देखा जाता है, जहां आप तमाम विफलताओं से गुजरते हुए कुछ नया, कुछ अजूबा या कुछ उपयोगी खोज लाते हैं। बचपन से ही थॉमस एडिसन के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले विद्युत से प्रकाश हासिल करने की तकनीक विकसित की या फिर उन आइंस्टीन के बारे में, जो हर रोज ट्रेन में बैठकर जाते हुए एक क्लॉक टॉवर को देखते थे और उसे देखते-देखते उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत तैयार कर दिया। या फिर उन वैज्ञानिकों के बारे में, जिन्होंने कई पदार्थों, कई गैसों और कई तकनीकों की खोज की। आमतौर पर माना यही जाता है कि वैज्ञानिक जब प्रयोगशाला में जुटते हैं, तो उनकी कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा यूरेका वाला क्षण आता है, जब उनके हाथ एक नई खोज लगती है। लेकिन आज के वैज्ञानिकों के साथ भी क्या ऐसा ही होता है? इसका जवाब पाने का एक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम उन वैज्ञानिकों से उनकी खोज के बारे में सुनें, जिन्हें इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है।

मसलन, हमारे सौर्य मंडल के बाहर के ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिक मिशेल मेयर की बात करें, तो हमें लगता है कि आसमान को निहारते हुए एक ऐसा क्षण आया होगा, जब उन्हें एक ऐसा ग्रह मिल गया होगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले इस वैज्ञानिक ने ऐसे किसी क्षण से ही इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें कुछ आंकड़े मिले, जिसका उन्होंने जब कई महीनों तक आकलन किया, तो कुछ संकेत मिले। तब तक वे स्थितियां ओझल हो चुकी थीं और अगले साल का इंतजार करना पड़ा। अगले साल भी वही नतीजे मिले, तो लगा कि एक एक्सोप्लैनेट उनके हाथ आ गया है। कुछ ऐसी ही बात पिछले साल चिकित्सा का नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिक जिम एलीसन ने कही है। कैंसर को मात देने में इम्यून सिस्टम की भूमिका खोजने वाले इस वैज्ञानिक का कहना है कि यह ऐसे लोगों से ही संभव हो पाता है, जिनमें जिज्ञासा भी हो और लगन भी। वे पहले जानकारियां हासिल करते हैं, फिर उनसे मिले आंकड़ों से जूझते हैं और सच को समझने की कोशिश करते हैं। इस साल चिकित्सा का नोबेल जीतने वाले ग्रेग एल सेमेन्जा इस बात को दूसरी तरह से कहते हैं। उनका कहना है कि किसी खोज तक पहुंचना उपलब्ध आंकड़ों से पहेली हल करने जैसा हो जाता है। लीथियम बैटरी की खोज के लिए इस साल रसायन विज्ञान का नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिक एम स्टेनले विटंघम का कहना है कि यह काम तेल का कुआं खोदने की तरह है। अंत में दस फीसदी कुओं से ही तेल मिल पाता है।

दरअसल, जब हम एक वैज्ञानिक के बारे में सोचते हैं, तो हमारे ध्यान में एक ऐसा व्यक्ति आता है, जो लगातार प्रयोगशाला में सिर खपाता है और फिर आखिर में कुछ हासिल करके निकल आता है। यह सोच दरअसल उस युग की कहानियों से बनी है, जब विज्ञान अपने प्रारंभिक दौर में था। विज्ञान के साथ ही हमारी प्रयोगशालाओं का भी काफी विकास हो चुका है। अब ज्यादातर मामलों में अंतिम नतीजे कंप्यूटरों पर हुए लंबे आकलनों के बाद ही निकाले जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि विज्ञान अब आंकड़ों में उलझकर नीरस हो गया है। नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिकों ने उल्टे इसे दिलचस्प ही बताया है।

भविष्य से उम्मीदें

ग्लोबल एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.20 से घटाकर 5.80 प्रतिशत कर दिया। मूडीज के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती से काफी प्रभावित है और इसके कुछ कारक लंबे समय तक असर डालने वाले हैं। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुस्ती का कारण निवेश में कमी है, जिसने बाद में रोजगार सृजन में कमी और ग्रामीण इलाकों में वित्तीय संकट के कारण खपत पर भी असर दिखाया। मूडीज को भविष्य से उम्मीदें दिखायी दे रही हैं, पर वर्तमान खासा नाउम्मीद करने वाला ही दिख रहा है। पर बात सिर्फ विकास दर में कमी की नहीं है। मूडीज ने कॉपोरेट टैक्स में कटौती और कम जीडीपी वृद्धि दर के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मूडीज का आकलन है कि सरकार के लक्ष्य से 0.40 फीसद अधिक होकर राजकोषीय घाटा 3.70 फीसद पर पहुंच सकता है। मूडीज का यह आकलन सचाई के करीब ही लगता है कि ''अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से वास्तविक जीडीपी में पांच फीसद की वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन भारत के संदर्भ में यह कम है।' भारत जैसी अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति से विकास करना है, तब जाकर भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति संभव हो पाएगी। इसलिए पांच प्रतिशत की विकास दर पर अमेरिका भले ही जश्न मना ले, पर भारत के लिए यह विकास दर निराशाजनक ही मानी जाएगी। मूडीज का ने बहुत महत्त्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा किया है कि निवेश में सुस्ती है। तमाम उद्योग निवेश नहीं कर रहे हैं। तमाम उद्योगों को लगता है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती पर, अर्थव्यवस्था में मांग की मजबूती पर भरोसा नहीं है। इसलिए वह नया निवेश लगाकर अपनी रकम फंसाना नहीं चाहते हैं, पहले वो सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि हर मांग में तेजी आ जाए, तब ही नई क्षमताओं का निर्माण किया जाए, नया निवेश किया जाए। ऐसी सूरत में सस्ती दर पर कर्ज देकर भी कुछ खास संभव नहीं है, जब उद्योगपति नया निवेश करना ही नहीं चाहते, तब उन्हें सस्ते कर्ज से भी प्रेरित नहीं किया जा सकता है। यानी यहां पर रिजर्व बैंक के आसान मौद्रिक नीति की सीमा भी साफ हो जाती है और साफ हो जाता है कि एक हद के बाद रिजर्व बैंक भी सार्थक नीतिगत हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

परिधि/ विशाल तिवारी

नेक इरादे पर फिजूल बहस

तमिलनाडु के महाबलीपुरम में भारत और चीन के बीच शिखर वार्ता तो हर किसी की र्चचा के केंद्र में रहा मगर महफिल लूट लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समुद्र तट पर सफाई के दृश्य ने। सुबह तट की सैर करते वक्त वहां पड़े कचरे को उठाने और सफाई के संदेश ने सोशल मीडिया के सागर में एक बार फिर स्वच्छता अभियान पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हिलोरें लेने लगीं। किसी की नजर में इसे सफाई के नाम पर नाटक करार दिया जाने लगा तो किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्य उनकी विराट छवि को प्रदर्शित करता है। इसमें उनकी सचाई दिखती है।अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की ये कवायद बनावटी थी, बावजूद इससे निकले सकारात्मक संदेश को खारिज नहीं किया जा सकता है। बतौर प्रधानमंत्री व्यक्ति के कार्यकलापों का एक विशेष प्रभाव होता है। और नरेन्द्र मोदी ने इस प्रभाव का बखूबी इस्तेमाल किया है। विशेषकर स्वच्छता अभियान में इसका असर भी दिखता है। मोदी के सत्ता आरोहण से पहले तक आमजन में स्वच्छता अभियानों को लेकर प्रतीकात्मक धारणा थी। जनता नेताओं द्वारा इसे तस्वीर खिंचाऊ कार्यक्रम से ज्यादा महत्त्व नहीं देते थे। ठोस और ईमानदार पहल के अभाव में जनता भी ऐसी कवायदों के प्रति गंभीर नहीं हो पाती है। महाबलीपुरम के वीडियो से दो महत्त्वपूर्ण संदेश निकले-पहला; विदेशी मीडिया की मौजूदगी में भारत का पर्यावरण को लेकर एक मजबूत दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ। दूसरा; देश में तटीय पर्यावरण को लेकर भी संदेश का प्रचार-प्रसार हुआ है। बताते चलें कि भारत के पूर्व और पश्चिम में कुल 7517 किलोमीटर समुद्र तट हैं। इसमें गोवा भी शामिल है, जिसके खूबसूरत तट दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। आज भी दुनिया भर में समुद्री प्रदूषण लेकर जागरूकता की बेहद कमी है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30-35 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक पैकिंग सामग्री और बैग्स सीधे ही समुद्र में डम्प किए जाते हैं। जबकि लगभग 200 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक कचरा विभिन्न नदियों के माध्यम से महासागरों में पहुंचता है। इन सबसे इतर प्रधानमंत्री को भी इस बात पर मंथन करना चाहिए कि आखिर उनका सामान्य सा कदम भी विवादों से परे क्यों नहीं रहता, उस पर संशय के बादल क्यों मंडराने लगते हैं? इसके उलट आलोचकों को भी ऐसे मसले पर ''प्रधानसेवक' के साथ चलना चाहिए।

गांधी से लेनिन की कैसी तुलना

रामचंद्र गुहा

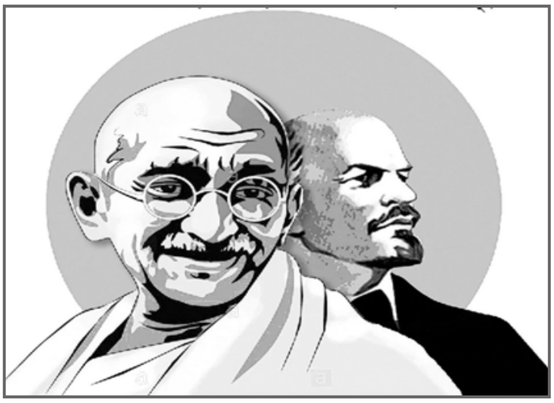

मैं कूटनीतिज्ञ इवान मैस्की की डायरी पढ़ रहा था। मैस्की 1932 से 1943 तक ब्रिटेन में रूस के राजदूत के रूप में सेवारत थे। वह इतिहास और भाषा विज्ञान के विद्वान थे। अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे। वह हिटलर और स्टालिन के दौर, सोवियत-नाजी संधि और उसकी टूट के गवाह रहे थे। मैस्की की डायरियां स्वाभाविक ही ब्रिटिश और यूरोपीय घटनाओं, व्यक्तित्वों पर केंद्रित है। हालांकि पुस्तक के 12वें पृष्ठ पर एक भारतीय राजनेता का अकेला और दिलचस्प विवरण है। महात्मा गांधी के कुछ समय के लिए कांग्रेस से अवकाश लेने की खबर सुनकर मैस्की ने 4 नवंबर, 1934 को डायरी में लिखा है, 'मेरे पास फिलिप मिलर की लिखी पुस्तक लेनिन ऐंड गांधी है, जो 1927 में वियना से प्रकाशित हुई थी। इसमें लेखक दो नेताओं के रेखाचित्र बहुत ही कुशलता से उकेरता है और उन्हें अपने समय के दो समान कद्दावर बताता है। लेकिन...लेनिन एक ऐतिहासिक मों ब्लां (आल्पस का सबसे ऊंचा पर्वत) हैं, मानवता के हजार साल के विकास में एक उज्ज्वल मार्गदर्शक शिखर हैं, जबकि गांधी महज एक कागजी पहाड़, जो एक संदिग्ध प्रकाश के साथ दसेक वर्षोंके लिए चमके थे, फिर तेजी से बिखर गए। वह कुछ ही वर्षों में इतिहास के कूड़ेदान में भुला दिए जाएंगे। समय और घटनाएं बहुमूल्य धातुओं को हल्के नकलचियों से अलग कर देती हैं।'

मैस्की वस्तुतः लेनिन द्वारा स्थापित सोवियत राज्य के एक ईर्ष्यालु निष्ठावान कर्मचारी थे। लेकिन इसके 13 साल पहले ही एक युवा भारतीय मुंबई के श्रीपद अमृत डांगे ने भी लेनिन को गांधी से ऊपर बताते हुए निबंध लिख दिया था। 1921 में प्रकाशित डांगे की इस पतली पुस्तक का नाम था- गांधी बनाम लेनिन। डांगे के तर्क थे- 'गांधी एक प्रतिक्रियावादी विचारक थे, जो धर्म और व्यक्तिगत विवेक के पक्ष में थे। दूसरी ओर, लेनिन ने आर्थिक उत्पीड़न की संरचनात्मक जड़ों की पहचान की और सामूहिक कार्रवाई करते हुए उत्पीड़न समाप्त करने की मांग की।' डांगे कभी रूस नहीं गए थे, न उन्होंने अपने नेता को अपनी आंखों से देखा था, फिर भी वह विश्वास के साथ कह सकते थे कि बोल्शेविकों ने रूस से किया 'भूमि, रोटी व शांति' का अपना वादा पूरा कर दिया है। छह वर्ष बाद ब्रिटिश संसद के एक ऐसे वामपंथी सदस्य ने गांधीजी को खुला पत्र लिखा, जो भारत में ही जन्मे, पले-बढ़े थे। शपूजी दोराबजी सकलतवाला ने गांधीजी पर भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि गांधीजी ने चरखा आंदोलन से मशीनरी, भौतिक विज्ञान और भौतिक विकास पर हमला बोला। शपूजी ने गांधीजी के साथ कमाल अतातुर्क, सन येत-सेन और लेनिन की अनुचित तुलना करते हुए लिखा, 'जहां इन नेताओं ने मुखरता और निडरता से लोगों की अव्यक्त आवाज को व्यक्त किया, वहीं गांधीजी ने भारतीयों को गुलाम आज्ञाकारिता और इस विश्वास के लिए तैयार किया कि वे पृथ्वी पर श्रेष्ठ लोग हैं।'

> “ एक दौर के लेनिनवादियों की राय के विपरीत विद्वानों और आम लोगों के बीच भी गांधीजी की वैश्विक प्रतिष्ठा लेनिन से कहीं बेहतर है। ”

शपूजी के पत्र के 1927 में प्रकाशन के दो वर्ष बाद हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के भगत सिंह सामने आए। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हो चुके भगत सिंह ने बयान जारी कर दावा किया कि उनका कृत्य अहिंसा के उस यूटोपियन युग का अंत है, जिसकी निरर्थकता के प्रति युवा पीढ़ी किसी भी शक के साये से परे आश्वस्त है। इस क्रांतिकारी ने युवा भारतीयों से आग्रह किया कि वे गांधी से मुंह मोड़ लें और उसकी जगह लेनिन की हिंसक क्रांति की राह पर चलें। इवान मैस्की की ही तरह 1920 और 1930 के दशक के भारतीय वामपंथी लेनिन की पूजा करते थे और गांधी से घृणा। शपूजी ने दावा किया कि लेनिन के रूस ने पूरी मानवता को रास्ता दिखाया। गांधी को सलाह भी दी गई थी कि 'वह अपने कार्यक्रम को छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं, हमारे कार्यकर्ताओं, किसानों और युवाओं को संगठित करने के लिए आध्यात्मिक भावुकता के साथ नहीं, बल्कि एक निर्धारित उद्देश्य के साथ काम करें।' लेकिन जैसा कि हुआ, लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन ने श्रमिकों, किसानों और अनेक युवाओं को पूरी निर्ममता से दंडित किया। 1930 के दशक का अंत आते-आते साफ हो गया कि सोवियत क्रांति राजनीतिक और आर्थिक, दोनों ही रूपों में एक मनहूस आपदा थी, लेकिन इसके बाद भी काफी समय तक कुछ पश्चिमी सुधारवादियों के बीच इस क्रांति के संस्थापक के लिए भावुकता बनी रही। संडे टाइम्स, लंदन में जनवरी 1972 में प्रकाशित एक लेख मैंने हाल ही में देखा है, जिसमें आलोचक सिरिल कोनोली ने लेनिन को ज्यादा महान बताते हुए लिखा है, 'अगर लेनिन भी गांधी की तरह लंबा जीते, तो स्टालिन नहीं हो पाते। तब क्या कोई हिटलर भी होता?' कोनोली को लगता है, हिटलर और नाजीवाद के उभार को लेनिन रोक लेते। डांगे की तरह कोनोली भी आश्वस्त थे कि लेनिन की विरासत आधुनिक दुनिया में ज्यादा प्रासंगिक रहेगी।

गौर कीजिए, कोनोली ने 1972 में यह लेख तब लिखा था, जब लेनिन के रूस में श्रमिकों को कोई अधिकार हासिल नहीं था, जबकि गांधी के भारत में वे ज्यादा वेतन और बेहतर सेवा शर्तों के लिए हड़ताल कर सकते थे। विडंबना यह कि डांगे और मैस्की पार्टी द्वारा भुगतान-पोषित थे, कोलोनी तो उच्च वर्ग के ऐसे उदारवादी थे, जो अच्छे भोजन व शराब के शौकीन थे। लेनिन अगर उनके देश पहुंच जाते, तो कोनोली भी उनके पहले शिकारों में एक होते। संयोग से लेनिन को भी अच्छा भोजन और बढ़िया शराब पसंद थी, दूसरी ओर, कथित बुर्जुआ प्रतिक्रियावादी गांधी एक आम कार्यकर्ता या किसान की तरह रहते थे। सोवियत रूस में जो कम्युनिस्ट नेता सत्ता में थे, वे रईसों की तरह रहते थे।

गांधी के छह महीने बाद लेनिन पैदा हुए थे। दोनों समकालीन थे, तो यह भी दोनों की तुलना का एक बड़ा कारण रहा है। भारत ने हाल ही में गांधी की 150वीं वर्षगांठ को धूमधाम से, तमाम आलोचनाओं के साथ, मनाया है। यह देखना रोचक होगा कि रूस और दुनिया लेनिन की 150वीं वर्षगांठ को कैसे मनाती है? मैं सोचता हूं, यह बोलना यथोचित होगा कि कुल मिलाकर, विद्वानों और आम लोगों के बीच भी, मरणोपरांत गांधीजी की वैश्विक प्रतिष्ठा लेनिन से बेहतर है। आज दुनिया में अहिंसा व परस्पर विश्वास, सद्भाव के भारतीय पुरोधा गांधी का ही नैतिक और राजनीतिक अनुसरण होने की अधिक संभावना है। वही हैं- मानवता के हजार साल के विकास में एक उज्ज्वल मार्गदर्शक शिखर।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भौतिकी का नोबेल

दूसरी धरती की तलाश के लिए जद्दोजहद

अभिषेक कुमार सिंह

इस साल के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले तीनों साइंटिस्टों कनाडाई मूल के अमेरिकी जेम्स पीबल्स और स्विट?ज़रलैंड के माइकल मेयर व डिडियर क्वेलोज की खोजें, असल में इस कायनात में इंसानियत की जगह की खोज पर केंद्रित हैं। जहां पीबल्स एक ओर अपनी थ्योरी से साढ़े 14 अरब साल पहले हुई बिग बैंग यानी महाविस्फोट की घटना के बाद ब्रह्मांड के विकास के बारे में इंसानी समझ में नए अध्याय जोड़ती है, तो दूसरी ओर स्विस वैज्ञानिकों मेयर और क्वेलोज ने सूर्य की तरह एक तारे की परिक्रमा करने वाले एक जिस एक्सोप्लैनेट (परा-ग्रह) को खोजा है, उससे पृथ्वी की तरह माहौल वाले ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को बल मिलता है। समग्रता में देखें तो तीनों वैज्ञानिकों की कवायद यूनिवर्स की ऐसी खोजबीन के बारे में है, जो समूचे ब्रह्मांड में मानव के अकेलेपन के जवाब की खोज पर जाकर ठहरती है।

सनातन सवाल है कि क्या इस कायनात में कुछ और ऐसी पृथ्वियां हैं, जो जिंदगी से लबरेज़ हों? सदियों से इंसान पृथ्वी के पार जीवन की तलाश में लगा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में इस खोजबीन में ज्यादा तेजी आई है और ब्रह्मांड में, खास तौर से हमारे सौरमंडल के नजदीकी इलाके में ऐसे कई ग्रह खोज लिए गए हैं, जिन्हें आकार-प्रकार के मामले में हमारी पृथ्वी जैसा ही बताया जा रहा है। इनमें भी ज्यादा नजर उन ग्रहों पर है, जहां जीवन के लिए जरूरी वातावरण का थोड़ा-बहुत संकेत मिलता हो।

असल में, वैज्ञानिकों ने ठीक वैसे ग्रहों पर ध्यान लगाया है जो संरचना यानी आकार-प्रकार में पृथ्वी जैसे ही हैं और जिनका हमारी तरह कोई सौरमंडल भी है। वर्ष 2015 में भी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के खगोलविदों ने ऐसी ही एक सुपरअर्थ का पता लगाया था। यह हमसे महज 14 प्रकाशवर्ष दूर स्थित है। 'वुल्फ 1061-सी' नामक इस ग्रह के बारे में भी दावा किया गया था कि जीवन की संभावना के मामले में यह हमारी पृथ्वी के करीब हो सकता है। वुल्फ 1061-सी पृथ्वी से सिर्फ चार गुना बड़ा है और इस पर पृथ्वी के मुकाबले 1.8 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। अपने तारे (उस सौरमंडल का मुखिया यानी सूरज) की तरफ रहने वाला इसका एक पक्ष भयानक रूप से तपता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ काफी ठंड है। इन दोनों के बीच कुछ स्थान ऐसा है, जहां जीवन पनपने की संभावना बनती है।

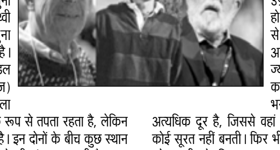

हालांकि, अभी तक जिन सुपर-पृथ्वियों का पता चला है, वे हमसे सैकड़ों-हजारों प्रकाशवर्ष दूर हैं। इस मामले में कुछ समय पहले खोजे गए गलीज-667-सीसी (22 प्रकाशवर्ष दूर) और वल्कैन कहलाने वाली 16 प्रकाशवर्ष दूर स्थित नई सुपरअर्थ से ही कुछ उम्मीदें बंधती हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत हमारे काफी नजदीक हैं। वैसे इसके संकेत 90 के दशक में ही मिलने लगे थे कि सुदूर ब्रह्मांड में कहीं और धरती जैसा ग्रह हो सकता है। वर्ष 1992 में पहली बार एक पल्सर के आसपास ग्रह जैसा कुछ होने का अनुमान लगाया गया और इसके अगले 25-30 सालों में हाल यह है कि अब तक 2,675 स्टार सिस्टम्स में फैले हुए पृथ्वी जैसे करीब 3900 ग्रहों की सूची जारी हो चुकी है, हालांकि इनमें से ज्यादातर ग्रह बहुत अजीब हैं। कोई बहुत ज्यादा ठंडा है तो कोई गर्म। कहीं जहरीली गैसों की भरमार है तो कोई सूर्य के अत्यधिक दूर है, जिससे वहां जीवन की संभावना की कोई सूरत नहीं बनती। फिर भी इनमें करीब 350 ग्रहों को धरती से मिलता-जुलता माना जा सकता है। संभावना है कि इनमें से किसी में जीवन हो सकता है।

यहां एक अजब विरोधाभास यह है कि अब से पांच सौ साल पहले तक सूरज, चांद, सितारों को एक साथ दिखाने वाला जो भी मॉडल तैयार किया जाता था, उसके केंद्र में पृथ्वी ही हुआ करती थी। फिर कॉपरनिकस ने पृथ्वी को धकियाकर सूरज को इस मॉडल के केंद्र में ला दिया और उनके कोई सौ साल बाद गैलिलियो ने इस तस्वीर को इतना बदल दिया कि पृथ्वी का ब्रह्मांड की धुरी होना तो दूर, बड़ी तस्वीर में इसका मुकाम ही खोजना मुश्किल हो गया। लेकिन पर्यावरण-त्रासदियों के चलते अंतरिक्ष में जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियों वाला ग्रह ढूंढ़ निकालना हमारी दिलचस्पी के केंद्र में आ गया है। स्पेस में जीवन की तलाश के अभियान इधर इतने जोरों पर हैं कि सिर्फ सुपरअर्थ ही नहीं, वैज्ञानिकों ने बाह्य अंतरिक्ष में पूरे-पूरे सौरमंडल भी खोज लिए हैं जो तकरीबन हमारे सोलर सिस्टम जैसे हैं। जैसे, वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने 39 प्रकाशवर्ष दूर स्थित एक ऐसा नया सोलर सिस्टम ढूंढ़ निकाला, जिसमें ठीक हमारे सौरमंडल की तरह ही सात ग्रह (प्लैनेट) हैं। वैज्ञानिकों ने इसके सूर्य को 'ट्रैपिस्ट-1' का नाम दिया था। इस सौरमंडल के ग्रह भी दिखने में धरती से काफी मिलते-जुलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां जीवन के लिए अनुकूल हालात हो सकते हैं।

बहरहाल, इस बात से ज्यादातर वैज्ञानिक सहमत हैं कि बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की खोजबीन करनी है, तो सबसे पहले पृथ्वी जैसे ग्रहों का पता लगाना होगा। यदि बाह्य अंतरिक्ष में कोई पृथ्वी जैसे आकार-प्रकार व संरचना वाला ग्रह मिल जाता है, तो उसकी सूक्ष्म पड़ताल करके जीवन की संभावना का पता किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि हम तब कह सकेंगे कि इस कायनात में हम अकेले तो नहीं।

मुद्दा

धारदार बने कृषि नीति

सुशील कु. सिंह

यह आंकड़ा माथे पर बल ला सकता है कि अमेरिका में किसान की सालाना आय भारतीय किसानों की तुलना में 70 गुना अधिक है। जिन किसानों के चलते करोड़ों का पेट भरता है वही खाली पेट रहें यह सभ्य समाज में बिल्कुल नहीं पचता। भारत में किसान की प्रति वर्ष आय महज 81 हजार से थोड़े ज्यादा है, जबकि अमेरिका का एक किसान एक माह में ही करीब 5 लाख रुपये कमाता है। आंकड़े यह भी स्पष्ट करते हैं कि भारत का किसान गरीब और कर्ज के बोझ के चलते आत्महत्या का रास्ता क्यों चुनता है? किसानों की समस्या इतनी पुरानी है कि कई नीति निर्धारक इस चक्रव्यूह में उलझते तो हैं पर उनके लिए शायद लाइफचेंजर नीति नहीं बना पा रहे हैं। अगस्त 2018 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा नफीस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें एक किसान परिवार की वर्ष 2017 में कुल मासिक आय 8,931 रुपये बताई गई। बहुत प्रयास के बावजूद नाबार्ड की कोई ताजा रिपोर्ट नहीं मिल पाई, परन्तु जनवरी से जून 2017 के बीच किसानों पर जुटाए गए इस आंकड़े के आधार पर इनकी हालत समझने में यह काफी मददगार रही है। रिपोर्ट यह दर्शाता है कि भारत में किसान परिवार में औसत सदस्य संख्या 4.9 है। इस आधार पर प्रति सदस्य आय उन दिनों 61 रुपये प्रतिदिन थी। दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार भारत का असली चेहरा देखना हो तो किसानों की सूरत झांकनी चाहिए। जब राज्यों की स्थिति पर नजर डाली जाती है तो किसानों की आय में गम्भीर असमानता दिखाई देती है। सबसे कम मासिक आय में उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा समेत पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा आदि शामिल हैं। जहां किसानों की मासिक आय 8 हजार से कम और 65 सौ से ऊपर है, जबकि यही आय क्रमशः पंजाब और हरियाणा में 23 हजार और 18 हजार से अधिक है। असमानता देखकर यह प्रश्न अनायास मन में आता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो परिप्रेक्ष्य लेकर केंद्र सरकार चल रही है वह कहां, कितना काम करेगा? पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों की आय में अंतर किया जाए तो यह साढ़े तीन गुना है। सवाल यह है कि क्या दोगुनी आय के साथ अंतर वाली खाई को भी पाटा जा सकेगा। खास यह भी है कि आर्थिक अंतर व्यापक होने के बावजूद पंजाब और उत्तर प्रदेश किसानों की आत्महत्या से मुक्त नहीं है। इससे प्रश्न यह भी उभरता है कि किसानों को आय तो चाहिए ही साथ ही वह सूत्र, समीकरण और सिद्धान्त भी चाहिए, जो उनके लिए लाइफचेंजर सिद्ध हो। जिसमें कर्ज के बोझ से मुक्ति सबसे पहले जरूरी है। सवाल यह है कि बीते 5 सालों में जिन राज्यों की ओर से कर्ज माफी का कदम उठाया गया, क्या उससे किसानों की हालत सुधरी? यह योजना सही है या गलत इसे स्पष्ट तौर पर कहना कठिन है पर इसका लाभ हुआ ही नहीं ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। सवाल यह है कि किसानों को राहत कैसे दिया जाए? भारत में किसान समाज और खेती का उपकरण कभी ढांचागत रूप में व्यापक नीति के दायरे में आया ही नहीं। किसान क्या चाहते हैं इस पर भी सरकारों ने ठीक से गौर नहीं किया। इतना ही नहीं उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकारों ने जो कदम उठाए वे भी ठोस नहीं सिद्ध हुए। सरकारों की गलती यह रही कि कम आय, बढ़ती लागत और नीतिगत दुर्व्यवहार के चलते जो कृषि संस्कृति को संकट आया उस समस्या से छुटकारा दिलाने के बजाय ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक हथकंडे अपनाए गए। सवाल यह है कि नीति बनाने वाले किस सूत्र और सिद्धान्त को अपनाएं कि किसान की हालत दीन-हीन की नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि की हो। इन सूत्रों का भी सहारा लेकर सरकार बड़ा परिवर्तन ला सकती है; मसलन सरकार को चाहिए कि किसानों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए। किसानों की दशा सुधारने के लिए देश में जल विकास की योजना को सबल किया जाए क्योंकि आधी ही कृषि गैर सिंचित है। किसानों को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अनुपात में प्रोत्साहित किया जाए। कृषि की तकनीक सस्ती हो, अनायास सरकारी हस्तक्षेप हटे और फसल की उचित कीमत मिले। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर सफलता दर सुनिश्चित की जा सकती है। जब तक किसानों को फलक पर खड़ा करने का प्रयास नहीं होगा और केवल इन पर भावनात्मक राजनीति करके वोट खींचा जाता रहेगा तब तक यह दुश्वारियों से बाहर नहीं निकलेंगे। यूरोप और अमेरिकन मॉडल को भी कृषि नीति में लाकर इनके लिए बेहतर प्रयास हो सकता है।

9 दिन के 'लोन मेले में खूब बंटा लोन, बैंकों ने दिया 81,700 करोड़ रुपए का कर्ज: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली(एजेंसी)।।

उद्यमियों, किसानों और दूसरे जरूरतमंदों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए शामियाना लगाकर खुले में आयोजित 'लोन मेले में सरकारी बैंकों ने नौ दिन में कुल मिलाकर 81,781 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया। बैंकों की ओर से यह आयोजन एक अक्टूबर से शुरू किया गया। वित्त सचिव राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि उद्यमियों और जरूरतमंदों तक सीधे पहुंच बनाने के इस कार्यक्रम के दौरान कुल 81,781 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। इसमें 34,342 करोड़ रुपए का नया ऋण शामिल है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सरकारी बैंकों के चीफ से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास उन कंपनियों की एक लिस्ट हैं जिनका लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) पर 40,000 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्रेटरी यह डाटा बैंकों को देंगे। सीतारमण ने यह भी कहा कि ये डाटा मिलने के बाद बैंक इन सभी एमएसएमई से मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वो इस रकम में कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। जिन कंपनियों पर यह रकम बकाया है उनका दावा है कि एमएसएमई पेमेंट के लिए छूट देने को तैयार हैं। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से यह निवेदन किया है कि वो सभी कंपनियों को लिखे कि ÷आपने दावा किया था कि एमएसएमई को इतनी रकम चुकानी है। क्या आप पेमेंट जल्दी चुकाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी कोशिश है कि एमएसएमई को दिवाली से पहले उनका बकाया मिल जाए। वित्त मंत्री ने बैंकों के विलय पर कहा कि पूरी प्रक्रिया सामान्य तौर पर चल रही है। एक बैंक बोर्ड के सभी सदस्य मेन बैंक बोर्ड में शामिल होंगे। प्रक्रिया को आसान बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बैठक में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (एनबीएफसी) और एमएसएमई को पर्याप्त फंड मुहैया कराने पर भी बातचीत हुई।

एयरबस हेलीकॉप्टर्स को पवन हंस के विनिवेश का मामला जल्द सुलझने की उम्मीद

नई दिल्ली(एजेंसी)।।

एयरबस हेलीकॉप्टर्स को उम्मीद है कि केंद्र सरकार पवन हंस लिमिटेड के विनिवेश से जुड़े मुद्दे का जल्द समाधान कर लेगी। इससे राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर कंपनी अपनी बेड़ा विस्तार की योजना पर आगे बढ़ सकेगी। वैश्विक हेलीकॉप्टर विनिर्माता कंपनी के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने यह बात कही। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने जून में पवन हंस के साथ पेरिस में एक सहमति ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत पवन हंस भविष्य में एयरबस से एच-145 और एच-225 की दो नई श्रेणियों के हेलीकॉप्टर की खरीद करेगी। एयरबस के भारतीय और दक्षिण एशिया परिचालन के हेलीकॉप्टर कारोबार प्रमुख आशीष सर्राफ ने कहा कि पवन हंस राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सेवाप्रदाता है। उसके पास बड़े पैमाने पर हेलीकाप्टर का अधिग्रहण करने की क्षमता है। मौजूदा समय में विनिवेश पर बातचीत के चलते कंपनी ने अपनी विस्तार योजना को रोका हुआ है। कंपनी को उम्मीद है कि सरकार इस मामले का जल्द समाधान कर लेगी ताकि पवन हंस अपना विस्तार कर सके। विनिवेश की प्रक्रिया शुरू होने के चलते पवन हंस ने अपनी विस्तार योजना को टाल दिया है। हालांकि 11 जुलाई को केंद्र सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए प्राथमिक सूचना ज्ञापन जारी किया है। हालांकि, यह ज्ञापन जारी करने के बाद से सरकार इच्छुक कंपनियों से रूचि पत्र जमा करने की तारीख को तीन बार विस्तार दे चुकी है। आखिरी बार सरकार ने 25 सितंबर को इसकी तारीख बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी। पवन हंस में सरकार की 51 और ओएनजीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी के बेड़े में 43 हेलीकॉप्टर हैं। कंपनी के पास पुराने डाफिन हेलीकाप्टर हैं। पवंन हंस के साथ साथ एयरबस हेलीकाप्टर्स भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि कैसे पुराने बेड़े के हेलाकाप्टरों के स्थान पर नई पीढ़ी के हेलीकाप्टर शामिल किए जाएं।

भारत में गैस पाइपलाइन, बुनियादी ढांचे पर 60 अरब डॉलर का निवेश: प्रधान

नई दिल्ली(एजेंसी)।।

भारत ऊर्जा संसाधनों के उपभोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गैस आपूर्ति और वितरण बुनियादी ढांचे को विकसित करने में 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर रहा है। देश में ऊर्जा उपभोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 2030 तक दोगुनी करके 15 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को यह बात कही। प्रधान ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान में देश में सभी ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस धीरे-धीरे भारत में कम कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर ईंधन के रूप में अपनी जगह बना रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार गैस बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है। इसमें देश के उत्तरी भाग को दक्षिण और पूर्व को पश्चिम भाग से जोड़ा जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने इंटरनेशनल थिंक टैंक की तीसरी बैठक में यहां कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम गैस पाइपलाइन और टर्मिनल बुनियादी ढांचे पर अनुमानित 60 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। यह काम पूरा होने के करीब या फिर उन्नत स्तर पर है। उन्होंने कहा, शहरी गैस वितरण नेटवर्क की पहुंच जल्द ही भारत की 70 प्रतिशत आबादी तक होगी। सरकार तेल और गैस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी का विकल्प तलाश रही है। देश में भविष्य के ऊर्जा स्त्रोतों के लिए जरूरी नवाचार के साथ निवेश लाने के लिए निजी क्षेत्र (घरेलू एवं विदेशी) की भूमिका अहम रहेगी।

36 प्रतिशत की वार्षिक दर पर लोन देनी वाली ऐप के खिलाफ गूगल ने उठाया बड़ा कदम

सैन फ्रांसिस्को (एजेंसी)।।

हिंसक लोन से बेहतर तरीके से निपटने के लिए गूगल ने प्ले स्टोर से उन एप्स को हटा दिया है, जो भ्रामक और हानिकारक प्रचार के जरिए 36 प्रतिशत की वार्षिक दर या उससे अधिक दर पर पर्सनल लोन दे रहे थे, जैसे पेडे लोन्स। एनगैजेट ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कहा कि एक प्रवक्ता ने बताया कि विस्तारित वित्तीय नीति इस वर्ष की शुरुआत से लागू की गई थी और ऐसा शोषको से यूजर (ग्रहकों) की रक्षा करने के लिए किया गया था। फैसले से प्रभावित हुए करदाता टेक दिग्गज कंपनी के फैसले से खुश नहीं हैं। यह नियम या तो उन्हें कम दरें करने या पूरी तरह से झुकाने का कार्य करते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऑनलाइन लेंडर्स अलायंस के सीईओ मैरी जैक्सन ने बार-बार कहा कि कंपनियों के व्यवहारों को अनुमति दी गई थी। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि प्रतिबंध वैध ऑपरेटरों के साथ-साथ उन ग्राहकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो वैध ऋण की तलाश में है।

सोना 230 रुपए चमका, चांदी भी मजबूत

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही तेजी के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 230 रुपए चमककर 39,370 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 110 रुपए की मजबूती के साथ बाजार बंद होते समय 46,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। विदेशों में सोना हाजिर 1.70 डॉलर की बढ़त के साथ 1,492.20 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। दिसंबर का अमेरिकी सोना वायदा भी 5.10 डज्ञॅलर चमककर 1,493.80 डॉलर प्रति औंस बोला गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि तकनीकी कारणों से आज सोने में मामूली तेजी रही। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध को लेकर हुई वार्ता को लेकर अब तक काफी सकारात्मक धारणा है, हालांकि वार्ता का सीमित विवरण ही सामने आ पाया है। इससे निवेशक पूंजी बाजार में निवेश के लिए तैयार हैं। इससे सोने की बढ़त सीमित रही। अंतररष्ट्रीय बाजार में चांदी हाजिर 0.04 प्रतिशत की मजबूती के साथ 17.57 डॉलर प्रति औंस पर पहुँच गई।

सरकार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए अनुकुल नियामकीय माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत: बिड़ला

नई दिल्ली(एजेंसी)।।

वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने अनुकूल नियामकीय माहौल सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि नए डिजिटल इंडिया के निर्माण के लिए फलता-फूलता दूरसंचार क्षेत्र जरूरी है। बिड़ला ने सोमवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2019 को संबोधित करते हुए कहा, जब हम दूरसंचार उद्योग की वृद्धि के समर्थन को प्रतिबद्ध हैं, तो हमें अनुकूल नियामकीय वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जरूरी निवेश किया जा सके।÷ उन्होंने कहा कि भारत में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं का आकार 60 करोड़ है। यह चीन के बाद सबसे ज्यादा है। बिड़ला ने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और रोबोटिक्स डिजिटल वृद्धि को आगे बढ़ाएंगे। बिड़ला ने कहा कि डिजिटल इंडिया 2.0 का उद्देश्य न्यू इंडिया का निर्माण करना और 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करना है। स्वीडन की दूरसंचार उपकरण वि निर्माता एरिक्सन ने सोमवार को घोषणा की है कि भारत में 5 जी सेवा के चालू होते ही वह देश में इसके लिए उपकरण बनाना शुरू कर देगी।

एरिक्सन के प्रमुख (दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिआनिया और भारत) नुनजिओ मिरतिलो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2019 में कहा, इस साल हम यह कह सकते हैं कि एक बार देश में 5 जी शुरू हो जाएगा तो हम अपने उत्पादन को 4 जी से 5 जी में बदलने के लिए तैयार हैं। हम भारत के लिए , भारत में 5 जी उपकरणों का उत्पादन करेंगे। कंपनी ने कहा कि भारत में उसका कारखाना है, जहां 4जी नेटवर्क उपकरण बनाए जा रहे हैं।

टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर भी सुस्ती, प्रत्यक्ष कर संग्रह अनुमान से 12 फीसदी कम

नई दिल्ली(एजेंसी)।।

देश में आर्थिक मंदी के बीच कर संग्रह में भी सुस्ती का दौर जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दोनों ही मोर्चों पर सरकार को राजस्व संग्रह में वर्ष 2019-20 के कर संग्रह अनुमान से कम सफलता मिल रही है। द प्रिंट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से 12 फीसदी कम हुआ है। यानी बजट अनुमान 17 फीसदी की जगह प्रत्यक्ष कर संग्रह धीमी गति से मात्र पांच फीसदी की दर को ही पा सका है। उधर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन भी मात्र 12 फीसदी की दर से बढ़ रहा है जबकि बजट अनुमान 15 फीसदी का है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन में पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के डेटा से पता चलता है कि अप्रैल से अगस्त के बीच प्रत्यक्ष कर संग्रह वर्ष के लिए कुल बजटीय कर संग्रह का केवल 21 प्रतिशत था,जो 2.76 लाख करोड़ रुपए है। 15 सितंबर को आए अग्रिम कर संग्रह ने भी इसमें कोई मदद नहीं की है। इस तारीख (15 सितंबर) तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.4 लाख करोड़ रुपए हुआ जो बजटीय लक्ष्यों का केवल 33 प्रतिशत ही है। वर्ष के पहले छह महीनों में जीएसटी संग्रह भी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह 5.26 लाख करोड़ रुपए के लक्षित बजट के 50 फीसदी से भी कम है। सिर्फ सितंबर 2019 में जीएसटी संग्रह घटकर 19 महीने के निचले स्तर 91,916 करोड़ रुपए पर रह गया। जीएसटी संग्रह में लगातार दूसरे महीने सुस्ती रही है, जबकि सरकार ने कर दरों में इस दौरान कोई बदलाव नहीं किया है। जीएसटी कलेक्शन में गिरावट को देखते हुए सरकार ने राजस्व प्राप्ति बढ़ाने सहित इसकी व्यापक रूप से समीक्षा कर जरूरी सुझाव देने को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की पहली बैठक मंगलवार (15 अक्टूबर) को होगी। जीएसटी परिषद के विशेष सचिव राजीव रंजन ने कहा, ''समिति की पहली बैठक मंगलवार यानी 15 अक्टूबर को होगी।'' उन्होंने कहा कि समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिये 15 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने पिछले सप्ताह इस समिति का गठन किया है। समिति को जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह बढ़ाने तथा कर चोरी रोकने के उपायों पर सुझाव देने का काम दिया गया है। एक जुलाई 2017 को शुरुआत होने के बाद जीएसटी की यह पहली व्यापक समीक्षा होगी। सरकार ने जीएसटी संग्रह तथा इसके प्रशासन को दुरुस्त करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए अधिकारियों की 12 सदस्यीय एक समिति गठित की है। समिति को राजस्व प्राप्ति में आ रही गिरावट को रोकने और राजस्व संग्रह बढ़ाने के बारे में आवश्यक उपायों के बारे में सुझाव देने को कहा गया है। समिति के गठन की शर्तों में जीएसटी का दुरुपयोग रोकने के उपायों तथा स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के कदमों समेत जीएसटी में संरचनात्मक बदलावों के बारे में सुझाव देना है।

प्याज-टमाटर के बाद अब लहसुन ने बिगाड़ा भोजन का स्वाद, 300 रुपए किलो हुआ भाव

बिजनेस डेस्क। प्याज, टमाटर के बाद अब लहसुन की महंगाई ने भोजन का जायका बिगाड़ दिया है। प्याज, टमाटर की महंगाई से लोग पहले से ही परेशान हैं और अब लहसुन का दाम भी आसमान छू रहा है। पिछले एक महीने में लहसुन का दाम तकरीबन 40 फीसदी उछला है, जबकि देश में इस साल लहसुन का उत्पादन पिछले साल से 76 फीसदी अधिक रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दुकानों पर लहसुन 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि लहसुन के थोक भाव में बीते दो सप्ताह में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है लेकिन रिटेल में लहुसन 250-300 रुपए प्रति किलो मिलने लगा है। जो कि दो सप्ताह पहले 150-200 रुपए प्रति किलो था। देश की प्रमुख लहसुन मंडी मध्यप्रदेश के नीमच, मंदसौर और राजस्थान के कोटा के कारोबारियों ने बताया कि बारिश के कारण स्टॉक में रखा लहुसन खराब हो जाने से सप्लाई का टोटा पड़ गया है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में मदर डेयरी के बूथ पर लहसुन 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जबकि दिल्ली-एनसीआर में सब्जी की दुकानों पर लहसुन 250-300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लहसुन के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और मध्यप्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में भी रिटेल में भाव 200 रुपए किलो से ज्यादा ही है। हालांकि नीचम मंडी में लहसुन का थोक भाव बीते 30 सितंबर को जितना था, तकरीबन उसी भाव पर बीते शनिवार को लहुसन बिका। नीमच मंडी में लहसुन का भाव 8,000-17000 रुपए क्विंटलनीमच में शनिवार को विभिन्न क्वालिटी के लहसुन का भाव 8,000-17000 रुपए क्विंटल था। कारोबारी सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, स्पेशल क्वॉलिटी का लहसुन हालांकि 21,700 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका।

संक्षिप्त समाचार

वेनेजुएला को कच्चे तेल के एवज में डीजल की आपूर्ति करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज वस्तु विनिमय व्यवस्था के तहत वेनेजुएला के कच्चे तेल के भुगतान के रूप में डीजल का निर्यात करेगी। कंपनी ने चार महीने के अंतराल के बाद अमेरिकी पाबंदी से प्रभावित वेनेजुएला से तेल आपूर्ति की शुरुआत की है। वेनेजुएला पर अमेरिकी पाबंदी जनवरी 2019 में लगी। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी तेल कंपनियों ने इस ओपेक देश के साथ वाणिज्यिक संबंधों में कटौती की। आरआईएल की अमेरिका में अच्छी-खासी मौजूदगी है। रिलायंस ने लातिन अमेरिकी देश से मार्च में तेल खरीद को सीमित कर दिया था। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ''आरआईएल डीजल जैसे स्वीकार्य उत्पादों की आपूर्ति वेनेजुएला को कर रही है और इसीलिए कच्चे तेल की खरीद करने की स्थिति में है। यह कदम अमेरिकी पाबंदियों के अनुरूप है क्योंकि स्वीकार्य उत्पादों की आपूर्ति के एवज में कच्चा तेल प्राप्त करने की अनुमति है। अमेरिकी पाबंदी के बाद कंपनियों ने वेनेजुएला से कच्चे तेल की सीधी खरीद पर रोक लगा दी थी और रूस की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट से तेल की खरीद शुरू की। रोसनेफ्ट वेनेजुएला तेल की अब प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

मांग घटने से सितंबर में चीन के आयात, निर्यात में गिरावट

बीजिंग। चीन के आयात और निर्यात में सितंबर महीने में उम्मीद से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू और वैश्विक स्तर पर मांग में कमी आना इसकी वजह रही। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी हुई। चीन के सीमाशुल्क प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, चीन का निर्यात इस साल सितंबर में पिछले साल इसी महीने की तुलना में 3.2 प्रतिशत गिर गया जबकि आयात 8.5 प्रतिशत घटा है। अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष सितंबर में 3.9 प्रतिशत घटकर 25.8 अरब डॉलर रह गया। अगस्त में यह 26.9 अरब डॉलर पर था। चीन ने शुक्रवार को हुए आंशिक अमेरिका-चीन समझौते के तहत अमेरिका के कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। समझौते में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और वित्तीय बाजार को खोलना भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता सिर्फ अस्थायी तौर पर राहत दे सकता है क्योंकि इसमें चीन की कंपनियों को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी जैसे मुद्दों को छोड़ दिया गया है।

फ्रांस की ऊर्जा कंपनी 'टोटल अडाणी गैस में 37.4 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी

नई दिल्ली। फ्रांस की ऊर्जा क कंपनी 'टोटल ने गौतम अडाणी के नेतृत्व वाली 'अडाणी गैस की 37.4 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की सोमवार को घोषणा की। गैस विपणन एवं वितरण कंपनी ने हालांकि सौदे के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी। दोनों कंपनियों के प्राकृतिक गैस के आयात और खुदरा बिक्री के लिए 50:50 के संयुक्त उद्यम की घोषणा करने के करीब एक वर्ष बाद यह ऐलान किया गया है। इस डील के बाद टोटल और अडाणी परिवार के पास 37.4-37.4 फीसदी शेयर रहेंगे। बाकी 25.2 फीसदी हिस्सेदारी आम निवेशकों के पास रहेगी। अदाणी परिवार के पास फिलहाल अडाणी गैस के 74.8 फीसदी शेयर हैं।

म्यूचुअल फंड कंपनियों ने एसआईपी से 6 महीने में 49,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए

नई दिल्ली। खुदरा निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) को तवज्जो दे रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के मुताबिक, म्यूचुअल फंड उद्योग ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में एसआईपी के जरिए 49,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए। यह एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-सितंबर 2018 में यह आंकड़ा 44,487 करोड़ रुपए था। म्यूचुअल फंड उद्योग ने कहा कि खुदरा निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अब भी एसआईपी सबसे उपयुक्त माध्यम बना हुआ है। ताजे आंकड़ों के मुताबिक, 2019-20 की अप्रैल-सितंबर अवधि में एसआईपी के जरिए 49,361 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस साल सितंबर तक एसआईपी के जरिए हर महीने औसतन 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। पिछले कुछ सालों में एसआईपी के जरिए निवेश में तेजी देखी गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में एसआईपी के माध्यम से करीब 92,700 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। 2017-18 में यह आंकड़ा 67,000 करोड़ से अधिक और 2016-17 में 43,900 करोड़ रुपए से अधिक था।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2019 शुरू, 5जी से लेकर नई टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली(एजेंसी)।।

देश की राजधानी दिल्ली में आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2019 का शुभारंभ हो गया है। यह तीन दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस मेले का आयोजन दूरसंचार विभाग के सहयोग से संचार क्षेत्र की कंपनियों के शीर्ष संगठन सीओएआई की ओर से एयरोसिटी में किया जा रहा है। इस मेले में दुनियाभर के 30 देशों से 500 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेने पहुंची हैं। एयरोसिटी में तीसरे इंडिया कांग्रेस की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। उद्घाटन संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद संचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों की मौजूदगी में किया। उद्घाटन समारोह में कुमार मंगलम बिड़ला, ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा, सीओएआई के राजन मैथ्यूज, भारती एयरटेल से रवि गांधी, फेसबुक से मोनिका देसाई, क्वालकॉम से पराग कैर, आईटीयू से मैलकॉम जॉनसन समेत सभी दिग्गज मोबाइल और टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। केन्द्रीय सूचना प्रसारण व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार जल्द ही 5जी स्पेक्ट्रम को लेकर खास कदम उठाएगी। 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर काफी समय से बात चल रही है। अब बिना देरी किए इसकी नीलामी की जाएगी। इस वित्त वर्ष 2019-20 तक 5 जी स्पेक्ट्रम को नीलाम कर दिया जाएगा।

प्रसाद ने कहा कि व्हाट्सएप पर अफवाहों तथा फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इससे अफवाह के अलावा लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं होंगी। सरकार डाटा मामले पर किसी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। हमलोग डाटा प्राइवेसी नियम, सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहे हैं। भारत में होने वाले इस बड़े टेक इवेंट की थीम इस बार रखी गई है।

इसे 9 अलग हिस्सों में बांटा गया है जिसमें इस विषय को 9 भागों में बांटा गया है जिनमें ऑग्युमेन्टेड ऐनालिटिक्स, ऑटोनोमस थिंग्स, फ्यूचर लॉजिस्टिक्स, इमर्सिव वर्ल्ड, इंटेलिजेंट एज, इन्वेन्टिव यूनिकॉर्न, एमहेल्थ, प्रिवेसी ऐंड एथिक्स और स्मार्ट स्पेसेज शामिल हैं।

लाखो रुपयों की शराब के साथ चार को दबोचा

थ्री व्हील टेम्पो में की जा रही थी महाराष्ट्र और राजस्थान बनावट की शराब की हेराफेरी

सूरत.

पुलिस ने वराछा क्षेत्र में से ओवर ब्रिज के निचे से महराष्ट्रा और राजस्थान बनावट की शराब के जत्थे के साथ तीन खेपियो को दबोच लिया. पुलिस ने शराब का जत्था और थ्री व्हील टेम्पो जब्त किया साथ ही तीन खेपियो को भी गिरफ्तार किया.

जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली सुचना के आधार पर पुलिस ने वराछा में अर्चना स्कूल के पास ओवर ब्रिज के निचे निगरानी करके वहा से एक थ्री व्हेल टेम्पो जब्त किया और टेम्पो की तलाशी ली थी उस दौरान टेम्पो के अंदर से महाराष्ट्र और राजस्थान बनावट की शराब का जत्था बरामद किया गया .पुलिस ने टेम्पों और शराब समेत १ लाख से अधिक का मुद्दामाल जब्त किया इसेक अलावा शराब की हेराफेरी करने में शामिल आरोपी लक्ष्मण राजपूत,मनोहर कुमावत,मोहन माली को गिरफ्तार कर लिया है.वराछा पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि शराब का जत्था कहा से लाये थे और किसके लिए लेकर आये थे.

२,८२ लाख की चोरी का मामला

पुलिस ने डेढ़ साल बाद आरोपियों को किया गिरफ्तार

सूरत.

वराछा के हिराबाग क्षेत्र में रिक्शा में सवार होकर सूरत स्टेशन जा रहे दंपती को निशाना बनाकर बदमाश उनका २,८२ लाख के माल भरा बैग उड़ाकर भाग आगये थे.इस मामलेम डेढ़ साल बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

मिली जानकारी के मुताबिक़ अडाजण आनंद महल रोड स्थित शांती विला फ्लैट्स निवासी दिलीप करू मकवाना गत 26 दिसम्बर की सुबह अपनी पत्नी के साथ गांव आये थे और वराछा के हिराबाग सर्कल में स्थित लक्जरी बस से उतरे थे । यहाँ से दंपती एक ओटो रिक्शा में सवार होकर सूरत स्टेशन की ओर जाने के लिए निकले थे इसी दौरान रिक्शा में पहले से बैठे सह यात्री के रूप बदमाशों ने उनका बैग उड़ा लिया था,बैग सोने चांदी जे गहने और नगद समेत २,८२ लाख का माल था। बैग चोरी होने की घटना से दम्पति के होश उड़ गए थे.उन्होंने वराछा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी.पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया । आरोपी की पूछताछ करने पर अपना नाम लिम्बायत के मीठी खाड़ी स्थित इस्लामी चौक निवासी असलम हसन शेख तथा लिम्बायत के कमरु नगर निवासी सलीम उर्फ़ सलीम डल्ली आमीन शाह बताया है । पुलिस ने दोनों के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही शुरू की है.

बदमाश उड़ा रहे कानून व्यवस्था की धज्जिया

मानदरवाजा क्षेत्र में चाक़ू से वार कर युवक की हत्या

सूरत.

शहर में बदमाश लूटपाट मचाने के साथ हत्या और हत्या की कोशिश जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देकर कानून व्यवस्था की धज्जिया उड़ा रहे है वही लोगो में यह आक्रोश है कि पुलिस ऐसे बदमाशों पर लगाम कसने और उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है. कपड़ा मार्केट में व्यापारी की हत्या के बाद गत रात मानदरवाजा टेनामेंट में चाकू से वार कर एक युवक की हत्तया से सनसनी फ़ैल गई.

मिली जानकारी के अनुसार मानदराजा स्थित बी-टेनामेंट निवासी गिरीश राणा जरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था.रविवार दोपहर को वह काम पर से घर आया था.इसके बाद शाम को घर से बाहर गया था तभी टेनामेंट में सीढ़ियों के पास किसी बदमाश के साथ उसका झगड़ा हुआ और उसी दौरान बदमाश ने उसपर चाकू से जानलेवा वार कर भाग निकला.गिरीश राण सीढ़ियों के पास ही लहूलुहान और तड़पता हुआ पड़ा था.घटना के बारे में पता चलते ही स्थल पर लोगो की काफी भीड़ जमा हो गई और फिर उसे १०८ एम्ब्युलेंस में नई सिविल अस्पताल में लेकर गए जहा डॉकटरो ने उसे मृत घोषित कर दिया.मृतक युवक कि पत्नी ने बताया की उन्हें नितिन जापान नामक बदमाश जान से मार देने की धमकी दे रहा था.उसी ने उनकी हत्या की है.सलाबतपुरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू की है.

नशे में धुत्त शिक्षक कक्षा में सोता पकड़ा गया, छात्रा से छेड़छाड़ आरोप

छोटाउदेपुर। शिक्षा के मंदिर में पियक्कड़ शिक्षक की शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें एक शिक्षक ने इतनी शराब पी कि उसे कोई होश नहीं रहा और वह स्कूल की एक कक्षा में खर्राटे भरने लगा। घटना है छोटाउदेपुर जिले की बोडेली तहसील के कठमांगवा प्राथमिक स्कूल की है। आश्चर्य की बात यह है कि स्कूल में परीक्षा चल रही है और शराब के नशे धुत्त शिक्षक परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के बीच खर्राटे मारते हुए सो रहा था।

प्रेमिका के शादी से इंकार करने पर बौखलाए आशिक ने घर में घुसकर की छेड़छाड़

सूरत। सूरत के अमरोली क्षेत्र में एक युवती द्वारा शादी से इंकार करने से बौखलाया प्रेमी उसके घर में घुस गया और शारीरिक छेड़छाड़ की। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक समेत उसकी माता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सूरत के अमरोली क्षेत्र निवासी युवती कॉलेज की छात्रा है। एक साल पहले फेसबुक पर युवती की निलय मोदी नामक युवक से दोस्ती हुई। जिसके बाद दोनों के बीच अक्सर मोबाइल पर बातचीत होने लगी और युवक-युवती को प्यार हो गया। कुछ समय के बाद युवक ने युवती के साथ शादी करने की इच्छा जताई। निलय के पिता और भाई युवती के घर शादी का प्रस्ताव भी लेकर गए। उस वक्त युवती के पिता ने सोच विचार कर जवाब देने की बात कर दोनों को रवाना कर दिया। जिसके बाद निलय लगातार युवती के चरित्र पर संदेह करने लगा और उसे पर नौकरी नहीं करने का दबाव डालने लगा। निलय की इस हरकत से परेशान होकर युवती ने उसके साथ प्रेम संबंध खत्म कर दिए। जिससे बौखलाया निलय युवती के घर पहुंच गया और प्रेम संबंध तोड़ने पर सवाल किए। युवती के घर में घुसे निलय ने उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। युवती की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। उस दौरान निलय की माता ने युवती और परिवार के खिलाफ जाति विषयक शब्दों का उपयोग करते हुए जान से मार देने की धमकी दी। युवती ने निलय और उसकी माता के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है।

व्यापारी हत्या प्रकरण

नाबालिग आरोपी पुलिस ने महराष्ट्र से किया डिटेन

सूरत.

बेगमवाड़ी में स्थित शुभम मार्केट के एक व्यापारी की दुकान में घुसकर की गई निर्मम हत्या के मामले में सलाबतपुरा पुलिस ने नाबालिग आरोपी को महाराष्ट्र के बुलढाणा से डिटेन कर लिया है. देर रात को पुलिस उसे सूरत लेकर आई थी. उससे पूछताछ करने के बाद ही हत्या का कारण स्पष्ट होगा.

सलाबतपुरा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सूरत के लिम्बायत स्थित प्रताप नगर का निवासी है. उसे महराष्ट्रा के बुलढाणा से पुलिस ने डिटेन किया और देर रात १२ बजे पुलिस की टीम उसे सूरत लाया गया था. उससे जरुरी पूछताछ करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगा कि उसने हत्या किन कारणों के चलते की है.आरोपी १७ साल का है .वह लिम्बायत के प्रताप नगर में रहता है. मंगल क्रियेशन नामक दूकान में व्यापारी तरुण सदाना की हत्या करने के बाद वह बुलढाणा भाग गया था.वहा से वह अपने के दोस्त के पास जानेवाला था इससे पहले ही उसे दबोच लिया. हत्या की घटना के चार दिन पहले ही वह दुकान में काम पर लगा था. पुलिस उससे जरुरी पूछताछ कर रही है.

बीआरटीएस बस की चपेट में राजस्थान के अधेड़ की मौत

सूरत। शहर वराछा क्षेत्र में सड़क पार कर राजस्थान के एक अधेड़ शख्स की बीआरटीएस बस की चपेट में आकर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर जमा लोगों की भीड़ में बस चालक को पकड़ पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के बांसवाडा निवासी मनीष जैन सूरत स्थित अस्पताल में उपचाराधीन साले को देखने आए थे। राजस्थान से अपनी कार में आए मनीष जैन ने अपनी कार वराछा के बरोडा प्रिस्टेज के निकट पार्क की थी। जहां से अस्पताल में साले को देखने गए और जब लौटे तो कार नहीं देख चौंक पड़े। पूछने पर पता चला कि उनकी कार टो कर ली गई है। कार छुड़ाने के लिए वह ऑटो रिक्शा पकड़ने सड़क क्रोस कर रहे थे। उस वक्त बीआरटीएस बस ने मनीष जैन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और बस ड्राइवर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही हादसे में गंभीर रूप से घायल स्थानीय लोगों ने मनीष जैन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

गुजरात के औद्योगिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र का बड़ा योगदान : नितिन पटेल

अहमदाबाद। उपने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र का बड़ा योगदान है। एमएसएमई क्षेत्र उद्योगों को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाता है। भरुच जिले के अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को नितिन पटेल की मौजूदगी में विभिन्न प्रकल्पों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर नितिन पटेल ने कहा कि राज्य में एमएसएमई की स्थापना के लिए जरूरी अनुमति लेने से कई छूट प्रदान की गई है। इतना ही नहीं तीन साल तक ऐसी अनुमति से मुक्ति देने का राज्य सरकार ने फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री ने भरुच जिले के अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र के जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए करीब रु. 65 करोड़ की लागत से एमएसएमई इकाई के लिए 10 एमएलडी के कॉमन एफ्लुन्ट ट्रीटमेंट प्लांट का पर्यावरण राज्य मंत्री जयद्रथसिंह परमार, सहकारिता राज्य मंत्री ईशवरसिंह पटेल, जीआईडीसी अध्यक्ष बलवंतसिंह राजपूत की मौजूदगी में शिलान्यास किया। साथ एमएसएमई उद्योगों के लिए एक्चैंज कन्वेयन्स पाइपलाइन, वेस्ट एक्सचैंज सेंटर का भी शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने रु. 1.25 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सीनियर सिटीजन एक्टिविटी सेंटर का नामकरण किया। सुषमा शांति नामक इस सेंटर में आवश्यक सुविधा मुहैया कराने के लिए सज्जन इंडिया लिमिटेड द्वारा रु. 51 लाख की सहायता की दी गई है।

उधना में किया गया आयुष्मान कार्ड केम्प का आयोजन

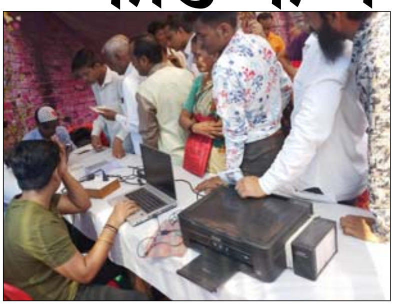

सूरत.

आवाज सेवाभावी ट्रस्ट और सूरत शहर शिवसेना द्वारा उधना क्षेत्र में स्थित कल्याण कुटीर सोसाइटी में आयुष्मान कार्ड केम्प का आयोजन किया गया था.

जानकारी के मुताबिक़ संस्था द्वारा लोकहित और जागृति के कार्यरकम तथा केम्प किये जाते है इसी प्रकार रविवार के दिन आयुष्मान कार्ड केम्प का आयोजन किया गया था. जिसमे २०० से ज्यादा लोगो ने लाभ लिया था.

शंकरसिंह की 'शक्ति दल' को पुनर्जिवित करने की कवायद

अहमदाबाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला ने फिर एक बार 'शक्ति दल' पुनर्जिवित करने की कवायद तेज कर दी है। वाघेला जब गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने शक्ति दल की स्थापना की थी। वर्ष 2003 में वाघेला के इस शक्ति दल के साथ राज्यभर से बड़ी संख्या में युवा जुड़े थे। लेकिन बाद में शक्ति दल का विसर्जन हो गया और वाघेला ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। अब एनसीपी से जुड़ने के बाद वाघेला ने शक्ति दल को पुनर्जिवित करने की कवायद तेज कर दी है और इसके लिए रविवार को अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर एक शक्ति दल सम्मेलन किया। हांलाकि सम्मेलन में उम्मीद के मुताबिक युवा जमा नहीं हुआ। इस मौके पर वाघेला ने राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बद्तर कानून व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होने का शक्ति दल के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर संघर्ष करना है। शासन में बैठा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है और यदि कोई बोलने का प्रयास करता है तो उसे खामोश कर दिया जाता है। शिक्षति युवाओं के भविष्य पर सरकार ने सवालिया निशान लगा दिया है। गौण पसंदगी बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए राज्य के 12 लाख युवा तैयार कर रहे थे और अचानक सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया। वाघेला ने कहा कि 40 लाख शिक्षति बेरोजगार युवा हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। शराबबंदी को लेकर वाघेला ने कहा कि इस मामले में सरकार को राज्य के प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद सरकार जो फैसला करती है उसका कड़ाई से अमल किया जाए।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)**